



राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रमांक एफ.6(1)(35)/रोल्स/निर्वा/2016/843

जयपुर, दिनांक :- 9-2-2017

प्रेषक :- मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषित :- समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) राजस्थान।

विषय:- ECI NET पोर्टल पर मतदान केन्द्रों पर आवश्यक सुविधाओं का
अंकन बाबत।

प्रसंग:- विभाग के पत्र क्रमांक एफ.6(1)(1)/रोल्स/निर्वा/2013/1058 दिनांक
04.02.2014 एवं 3714 दिनांक 29.09.2016 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आयोग के पत्र दिनांक 27 जनवरी, 2014 द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के केन्द्रों पर न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं (Basic minimum facilities) इसके पश्चात समय-समय पर (Assured minimum facilities) (AMF) सुविधायुक्त मतदान केन्द्र स्थापित करने के निर्देश किए गये थे।

गतवर्ष मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन से पूर्व मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन कर AMF सुविधायुक्त स्थानों का चयन कर मतदान केन्द्रों का पुनर्गठन/स्थान परिवर्तन आदि के प्रस्ताव टिप्पणी के साथ प्रेषित किए गए तथा AMF युक्त मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन के प्रस्तावों पर विभाग द्वारा परीक्षणोपरान्त स्वीकार कर, आयोग से अनुमोदन कराया गया है। इसके बाबजूद ECI NET पोर्टल पर मतदान केन्द्रों पर आवश्यक न्यूनतम सुविधा (AMF) की उपलब्ध सूचना का विश्लेषण करने के उपरान्त बिन्दुवार विशेषतौर पर निम्न कमियां पाई गई हैं। इससे प्रतीत होता है कि सूचना का अंकन उसी ढंग से ECI NET में नहीं किया गया।

1. कच्चा भवन में मतदान केन्द्र(1) :- विगत कई वर्षों से राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल भवनों का निर्माण यथा राजीव गांधी पाठशालाएँ, अटल सेवा केन्द्र आदि का निर्माण करवाने के उपरान्त उदाहरणार्थ, भरतपुर जैसे जिले में 230 मतदान केन्द्र कच्चे भवन में दर्शाये गये हैं इसी प्रकार अलवर में 18 तथा सीकर जैसे जिले में 72 मतदान केन्द्र कच्चे भवनों में स्थापित होना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है।

2. मतदान भवन जीर्ण-शीर्ण (3):- 19 जिलो में विभिन्न संख्या में मतदान केन्द्र भवन जीर्ण-शीर्ण भवनों में स्थापित किया जाना दर्शाया गया है हर वर्ष पुनरीक्षण से पूर्व मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन के पश्चात् पुनर्गठन की गहन प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्य करवाने के उपरान्त अलवर में 241, भरतपुर में 233, सवाई माधोपुर में 236 भवन जीर्णशीर्ण अवस्था में इंगित करना मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन का कार्य सन्देह उत्पन्न करता है।

3. मतदान केन्द्र सरकारी भवनों में स्थापित नहीं होना (4):— बिन्दु संख्या 4 में भीलवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़ जिलों में मतदान केन्द्र शत प्रतिशत सरकारी भवनों में दर्शाया गया है। परन्तु विभिन्न राजकीय भवनों के निर्माण यथा स्कूल भवन, अटल सेवा केन्द्र, पटवार घर आदि के निर्माण ग्राम पंचायत स्तर/ग्राम स्तर पर होने के उपरान्त गैर सरकारी भवनों की संख्या अलवर में 234, अजमेर में 145, बीकानेर में 170, चुरू में 180, जयपुर में 853, झुंझुनूं में 103, जोधपुर में 263, कोटा में 151, सीकर में 160 एवं उदयपुर में तो सैकड़ों मतदान केन्द्र सरकारी भवनों में स्थापित की सूचना दर्शाया जाना भ्रामक प्रतीत होती है।

4. संस्था/धार्मिक स्थलों पर मतदान केन्द्र (5) :— समय-समय पर मतदान केन्द्रों के भौतिक सत्यापन विशेष तौर से वर्ष 2016 में अर्हता दिनांक 01.01.2017 से पूर्व मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन के पश्चात् मतदान केन्द्रों का पुर्नगठन का कार्य गहन प्रक्रिया अपनाकर सम्पादन किया गया। इस प्रक्रिया के दौरान निजी/धार्मिक स्थलों के भवनों को जहाँ सरकारी भवन उपलब्ध हो वहाँ स्थानान्तरित करने के निर्देश देते हुए प्रस्ताव चाहे गये थे, मात्र दौसा, डूंगरपुर, झुंझुनूं एवं प्रतापगढ़ जिले में यह सूचना शून्य दर्शायी गई है। विशेष तौर से अलवर, बासंवाड़ा, भरतपुर, चुरू, जयपुर, सीकर एवं उदयपुर जिलों में यह संख्या सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शित हो रही है, जो सरकारी भवनों की उपलब्धता को मध्यनजर रखते हुए यह संख्या उचित प्रतीत नहीं होती है।

5. मतदान केन्द्र भू-तल पर न होना (7) :— बिन्दु संख्या 7 में अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, धौलपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, झुंझुनूं, नागौर, प्रतापगढ़ एवं टोंक ने शून्य सूचना दर्शायी गई है। जबकि चुरू ने 295, जोधपुर ने 220 इसी प्रकार अन्य जिलों ने भी मतदान केन्द्र भू-तल पर नहीं होने की स्थिति दर्शायी है। जबकि वर्ष 2016 में पुर्नगठन के दौरान इसी बिन्दु पर भी ध्यान आकर्षित किया गया था कि मतदान केन्द्र प्रथम मंजिल आदि पर स्थापित न होकर जहाँ तक सम्भव हो भू-तल पर ही स्थापित होना चाहिये। उसके उपरान्त भी बासंवाड़ा में 45, चुरू में 295, जयपुर में 12, जोधपुर में 220 एवं सिरोही में 12 तथा इसी प्रकार अन्य विभिन्न जिलों में भी मतदान केन्द्र भू-तल पर स्थापित नहीं होना दर्शाया गया है। जबकि वर्ष 2016 में मतदान केन्द्र के पुर्नगठन के दौरान प्राप्त प्रस्तावों में इस प्रकार की कोई टिप्पणी अंकित नहीं थी कि अमुख मतदान केन्द्र भू-तल पर न होकर प्रथम या अन्य किसी तल पर स्थापित का प्रस्ताव था। इस प्रकार की प्रविष्टियां सत्य से परे प्रतीत होती है।

6. दो दरवाजे के भवन (8) :— वर्ष 2016 में पुर्नगठन के दौरान मतदान केन्द्र के भवन दो दरवाजों वाले स्थापित करने के भी निर्देश थे जबकि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न नये आधुनिक भवनों के निर्माण के पश्चात् भी कई-कई जिलों में हजारों-सैकड़ों मतदान केन्द्र एक दरवाजे के भवन में स्थापित होने का अंकन का भी पुर्नरावलोकन किया जाना आवश्यक है।

7. मतदान केन्द्र पर पानी पीने की व्यवस्था (10) :- राज्य सरकार द्वारा गाँव-गाँव ढाणी-ढाणी में विभिन्न योजनाओं में नलकूपों के साथ-साथ हेडपम्पों के निर्माण कार्य करवाया गया है। कई जिलों में पानी का अभाव की संख्या दर्शायी गई है। जिसको भी देखा जाना आवश्यक है।

8. बिजली की व्यवस्था :- बिन्दु संख्या 11 में मात्र प्रतापगढ़ जिले में संख्या शून्य दर्शायी गई है। शेष जिलों में काफी मात्रा में मतदान केन्द्रों में बिजली का अभाव बताया गया है। जबकि राज्य सरकार द्वारा गाँव-गाँव, ढाणी-ढाणी में विभिन्न योजनाओं में बिजली की आपूर्ति का प्रबंध किया गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा विभिन्न पाठकर्मों में कम्प्यूटर शिक्षा के अध्ययन केन्द्र स्थापित किये गये हैं तथा अटल सेवा केन्द्रों पर इन्टरनेट सेवा भी संचालित की गई है। इसको मध्यनजर रखते हुए इन मतदान केन्द्रों में बिजली की व्यवस्था का न होना भ्रांति पैदा करती है।

9. महिला व पुरुषों के लिए शौचालय की व्यवस्था :- बिन्दु संख्या 13 में मात्र भीलवाड़ा, हनुमानगढ़ एवं प्रतापगढ़ जिलों में ही शत-प्रतिशत पुरुष एवं महिलाओं के लिए मतदान केन्द्रों पर शौचालय की व्यवस्था दर्शायी गई। शेष जिलों में अत्याधुनिक सरकारी भवनों के निर्माण, हाल ही में प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत योजना के अन्तर्गत घर-घर शौचालय के निर्माण को मध्यनजर रखते हुए मतदान केन्द्रों पर महिला व पुरुषों के लिए शौचालय की व्यवस्था न होने की सूचना की ओर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

10. रैम्प की व्यवस्था (14) :- भीलवाड़ा, धौलपुर, हनुमानगढ़, प्रतापगढ़ में मतदान केन्द्रों पर शत-प्रतिशत रैम्प दर्शाये गये हैं। हालांकि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर विशेष तौर से मतदान दिवस के अवसर पर जहाँ स्थाई रूप से भवन में रैम्प नहीं वहाँ मतदान भवन में अस्थायी तौर पर रैम्प की व्यवस्था की जाती है। जिन मतदान भवनों में रैम्प स्थापित नहीं है वहाँ इस ओर विशेष ध्यान देना आवश्यक है।

11. मतदान भवन में आवश्यक फर्नीचर की उपलब्धता (15) :- ज्यादातर मतदान केन्द्र सरकारी भवनों में ही उपलब्ध है जहाँ पर्याप्त मात्रा में फर्नीचर का अभाव के आंकड़े दर्शाया जाना सही प्रतीत नहीं होता है जिस पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है।

13. मतदान केन्द्र भवन तक सड़क की उपलब्धता (17) :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गाँव-गाँव एवं ढाणी-ढाणी सड़के/ग्रेवल रोड तथा सिमेंट सड़को का निर्माण कार्य गत कई वर्षों से निर्माणाधीन है उसके उपरान्त भी बहुत से जिलों में काफी संख्या में मतदान केन्द्र सड़क विहिन स्थानों पर स्थापित होना दर्शाया जाना सत्यता से परे प्रतीत होता है।

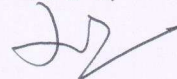
15. मतदान भवनों पर भवन के नाम का प्रदर्शन (22) :- तकरीबन समस्त मतदान केन्द्र या तो सरकारी भवनों में, निजी संस्थाओं के भवनों में स्थापित है जिन पर भवनों के नामों का अंकन होता है उसके उपरान्त कुछ जिलों यथा बीकानेर, चूरू, धोलपुर, कोटा एवं नागौर को छोड़कर मतदान केन्द्रों के भवनों पर नाम का संकेत नहीं दर्शाने की संख्या का अंकन का पुनरावलोकन किया जाना प्रस्तावित है।

16. नक्सली/विद्रोह प्रभावित क्षेत्र :- बिन्दु संख्या 23 में अलवर, बासंवाडा, बारां, बाडमेर, नागौर, भरतपुर, भीलवाडा, बून्दी, चित्तौड़गढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर जालोर, सिरोही आदि जिलों में LWE/insurgency प्रभावित क्षेत्र का अंकन किया गया है। जबकि राज्य में ऐसा कोई घोषित क्षेत्र है ही नहीं।

ECI NET पोर्टल पर मतदान केन्द्रों पर न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं AMF के क्रम में 26 तरह की सूचनाएं जिलों द्वारा आकड़े अपलोड किए हैं। वर्ष 2016 के मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन से पूर्व मतदान केन्द्रों की AMF को ध्यान में रखते हुए, भौतिक सत्यापन करवाया गया था तत्पश्चात भौतिक सत्यापन के आधार पर मतदान केन्द्रों पर AMF उपलब्ध नहीं है उन मतदान भवनो को AMF युक्त भवन में मतदान केन्द्र स्थापित करने के उपरान्त पुनर्गठन/ स्थान परिवर्तन को प्रस्तावों पर AMF की टिप्पणी के पश्चात ही प्रस्ताव भिजवाने पर विभाग द्वारा स्वीकार कर आयोग से अनुमोदित प्राप्त किया था। इसके उपरान्त अद्यतन स्थिति के अनुसार ECI NET पर जिलों द्वारा AMF की कमी वाले मतदान केन्द्रों की संख्या काफी मात्रा में दर्शाना विरोधाभास प्रतीत होता है। इस ओर आपका ध्यान आकर्षित कर लेख है कि ECI NET पर AMF के इन आकड़ों का पुनरावलोकन करते हुए अद्यतन सूचना दिनांक 28.02.2017 तक आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

संलग्न:- AMF रिपोर्ट।

भवदीया,



(डॉ० रेखा गुप्ता)

अति० मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर।

